

का विचार है और अब तक कितनी मात्रा में रई का आयात किया जा चुका है और कितनी मात्रा में आयात किया जाना है ;

(ग) देश में अच्छी किस्म और ग्रेड की रई के उत्पादन के बावजूद विदेशों के अधिक मूल्य पर रई का आयात करने और उन्हें मिल मालिकों को कम दरों पर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1978-79 में कितने मूल्य की कितनी मात्रा में किम किस्म की रई का आयात किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आशा भवती) : (क) जानकारी झकट्टी की जा नहीं है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय रई विभाग निगम की 1976-77 के रई मौसम के दौरान 14 लाख गार्ठे आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इस परिणाम में से 31 अगस्त, 1977 तक लगभग 228 करोड़ ६० के मूल्य की 8.18 लाख गार्ठे प्राप्त हो गई थी। उसके पश्चात् 1.84 लाख गार्ठे 15 फरवरी, 1978 तक प्राप्त हो गई। शेष परिमाण चालू रई मौसम 1977-78 की शेष अर्धवर्ष में प्राप्त हो जाएगा। 1977-78 के दौरान आयात की जाने वाली रई के मूल्य, किस्म और मात्रा से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा नहीं है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1976-77 में रई संभरण की स्थिति में काफी कमी आई। 1976-77 के आयात कार्यक्रम के उद्देश्य मुख्यतः देश में रई के मांग और संभरण के बीच की खाई का पाटना तथा रई की कीमतें स्थिर करना भी था। चूंकि आयातित रई ऊंचे मूल्यों पर प्राप्त हुई, सरकार ने इसे समान किस्म के देशी मूल्यों के मुकाबले कम दर पर बेचने का निश्चय किया।

(घ) सरकार ने 1978-79 के रई मौसम में रई के आयात के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया है।

सीमेन्ट की काले बाजार में विक्री

3916. श्री वेंगा भगत सिंह :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बैठक को सम्बोधित करने हुए यह स्वीकार किया था कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये के मूल्य का सीमेन्ट काला बाजार में बेचा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो काला बाजारी करने वाले लोग कौन हैं ; और

(ग) इस कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री ज्ञान फर्मानसिंह) :

(क) और (ख) - यह सही है कि उद्योग मंत्री ने 8 जनवरी, 1978 को उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए यह बताया था कि समूचे देश में सीमेन्ट की विक्री में होने वाली काला-बाजारी की खबरें मिली हैं तथा इसके जगिए विभिन्न लोगों द्वारा लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य की राशि अर्जित की जाती है। उपर्युक्त आंकड़े वास्तव में एक अनुमानित राशि थी, जो विभिन्न राज्यों में

निजी क्षेत्र के स्टॉकस्टों द्वारा बुले बाजार में लगभग 100 लाख मी० टन सीमेण्ट की बिक्री में विभिन्न मात्रा में की जाने वाली गड़बड़ियों से सम्बन्धित प्राप्त जानकारी पर आधारित थी।

(ग) बाजार में सीमेण्ट की उपलब्धता को बढ़ा कर तथा सीमेण्ट बाजार को बिक्रेता बाजार से क्रेता बाजार में परिवर्तित करके ही कालाबाजारी को समाप्त किया जा सकता है। सरकार विद्यमान एककों द्वारा अधिक उत्पादन किये जाने, प्रतिरिक्त क्षमता स्थापित करने तथा सीमेण्ट का परिरक्षण किये जाने तथा बेहतर उपयोग किये जाने जैसे अनेक कदम उठा रही है। अधिक महत्वपूर्ण कदमों में प्री-केल्सिनेटर लगाना तथा स्लैग, फ्लाई ऐश और अन्य पीजलाना पदार्थों का अधिक प्रयोग, स्थानीय स्लैग और चूने के पत्थर का प्रयोग करने हेतु स्टील सयंत्रों के स्थापना स्थल के समीप नए सीमेण्ट संयंत्रों की स्थापना, चूने के पत्थर के छोटे ढण्डारों के उपयोग हेतु छोटे सीमेण्ट सयंत्रों की स्थापना तथा नए एकको और बिन्तारों के निर्माण कार्यों में तेजी लाना शामिल है। सरकार ने देशी बाजार में सीमेण्ट की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु लगभग 10 लाख मी० टन सीमेण्ट का आयात करने का भी निर्णय किया है। सरकार बाजार पर आयातित सीमेण्ट के पड़ने वाले प्रभाव पर निगाह रखे है तथा सरकार द्वारा निश्चित स्तर तक सीमेण्ट के बिक्री मूल्यों को कम करने के प्रयास में यदि आवश्यक हुआ तो वह सीमेण्ट का और अधिक मात्रा में आयात जारी रखेगी। सरकार क्षमता को बढ़ाने के मार्ग में आने वाली विद्यमान रुकावटों का पता लगाने तथा इस बारे में आवश्यक सुधारामक कार्रवाई निश्चित करने को ध्यान में रखते हुए उद्योग के एक नवीन विस्तृत अध्ययन हेतु एक उच्चस्तरीय निकाय की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है।

4239 LS—4.

Cotton price

3917. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether cotton prices have fallen further in February, 1978;

(b) if so, whether they are now at an uneconomic level;

(c) whether several farmers growing cotton are likely to switch over to other crops as a result; and

(d) if so, what steps the Government is taking to help these farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) to (d). The prices of cotton in North Indian markets which were quite promising and reached levels comparable to 1976-77 started showing a decline in February, 1978, rather marginally. During 1976-77 cotton season prices spiralled to unprecedented levels on account of shortfall in domestic production of cotton. During 1977-78, the cotton production, estimated at 66 lakh bales is more than that of 1976-77 by 6.50 lakh bales. Further nearly 80 to 85 per cent of the estimated crop in Punjab and Haryana had been marketed by February, 1978 and the left-over stock consisted mainly of the third picking. Consequently the prevailing prices of the residual stock will have to be viewed with reference to their quality and demand.

Even then the prevailing prices are much above the minimum support prices announced by the Government. Government, therefore, do not expect that the farmers would switch over to other crops.

बिल्सी में सड़कों की समस्या

3918. श्री एस० ए० हनाल अलहाज : क्या नौबतुन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस हज़ारी की सेशन कचहरी के साथ वाली सड़कों की, जो कि बहुत खराब